



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 112]
No. 112]नई दिल्ली, ब्रह्मस्पतिवार, जून 1, 2006/ज्येष्ठ 11, 1928
NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 1, 2006/JYAIKSTA 11, 1928

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

जाँच शुरुआत संबंधी अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मई, 2006

विषय : चीन जन. गण. से स्टोल व्होल्स के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जाँच की शुरुआत

फा. सं. 14/8/2005-डीजीएडी.—मै. कल्याणी लेमर्ज लिमिटेड, पुणे और मै. व्हील्स इंडिया लिमिटेड, चेन्नई (जिन्हें एतदपश्चात आवेदक कहा गया है) ने 1995 में यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे एतदपश्चात अधिनियम कहा गया है) और सीमाशुल्क टैरिफ (पाइट वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण एवं क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिन्हें एतदपश्चात नियमावली कहा गया है) के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी के समक्ष एक याचिका प्रस्तुत की है जिसमें चीन जन. गणराज्य (जिसे एतदपश्चात "संबद्ध देश" या चीन जन. गण. कहा गया है) के मूल के अथवा वहाँ से निर्यातित वाणिज्यिक वाहनों के लिए फ्लैट बेस स्टील व्हील्स के पाटन का आरोप लगाया गया है और संबद्ध वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क लगाने के लिए पाटनरोधी जाँच शुरू करने का अनुरोध किया गया है।

और जबकि प्राधिकारी यह पाते हैं कि संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के पाटन, घरेलू उद्योग को क्षति और पाटन और क्षति के बीच कारणात्मक संबंध होने के पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य मौजूद हैं; प्राधिकारी एतदद्वारा उक्त नियमावली के नियम 5 के अनुसार कथित पाटन और घरेलू उद्योग को परिणामी क्षति और ऐसे कथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव के निर्धारण और ऐसे पाटनरोधी शुल्क की राशि की सिफारिश करने जिसे यदि लागू किया जाए तो यह घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी, के लिए पाटनरोधी जाँच की शुरुआत करते हैं।

1. विचाराधीन उत्पाद

वर्तमान याचिका में विचाराधीन उत्पाद चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहाँ से निर्यातित 16 "नामिनल व्यास से 20" नामिनल व्यास के फ्लैट बेस स्टील व्हील्स हैं जिनका प्रयोग वाणिज्यिक वाहनों में ट्यूब वाले टायर संबंधी अनुप्रयोग में किया जाता है। पहिए, रिम और डिस्क का संयोजन होते हैं जिनके साथ डिमाउटेबल रिंग होती है। रिमों एवं डिस्कों का उत्पादन अलग-अलग लाइनों में होता है और इन्हें पहिए के रूप में वेल्ड किया जाता है जिसे वाहनों के एक्स्प्रेस पर लगाया जाता है और वाहन चलाने के लिए टायरों के साथ फिट किया जाता है। वाणिज्यिक वाहनों में ट्रकों सहित बसें, लारियाँ, ट्रालर्स और ट्रेम्पों शामिल हैं।

पहियों को उपशीर्ष 870 870 में रेलवे या ट्रामवे रोलिंग स्टाक को छोड़कर बाहनों और उनके कलपुजों तथा अनुषंगी सामग्री की श्रेणी के अंतर्गत सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम के अध्याय 87 के अंतर्गत परिभासित किया गया है। तथापि यह सीमाशुल्क वर्गीकरण मात्र संकेतिक है और किसी भी तरह से वर्तमान जाँच के कार्य क्षेत्र पर बाध्यकारी नहीं है।

इस जाँच के प्रयोजनार्थ विचाराधीन उत्पाद का वर्ण “पहिये” के रूप में किया गया है।

2. घरेलू उद्योग की स्थिति

यह आवेदन मै. कल्याणी लेपस लिमिटेड, पुणे और मै. व्हील्स इंडिया लिमिटेड, चेन्नई द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है जो भारत में संबद्ध उत्पाद के एकमात्र उत्पादक हैं। आवेदक ने वर्तमान जाँच से संगत सूचना उपलब्ध कराई है। प्राधिकारी ने यह निर्धारित किया है कि (क) आवेदक कम्पनी के उत्पादन का भारतीय उत्पादन में बड़ा हिस्सा है; (ख) आवेदन का स्पष्ट रूप से समर्थन करने वाले घरेलू उत्पादकों का घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित समान उत्पाद के कुल उत्पादन में 50 प्रतिशत से अधिक हिस्सा है; और (ग) यह आवेदन घरेलू उद्योग द्वारा या उनकी ओर से किया गया है।

प्राधिकारी उपर्युक्त की जाँच करने के बाद यह निर्धारित करते हैं कि आवेदक नियम 2 के अर्थ के भीतर घरेलू उद्योग है और संबंधित नियमावली के नियम 5 के अनुसार आवेदन करने की योग्यता संबंधी मानदण्डों को पूरा करता है।

3. शामिल देश

वर्तमान जाँच में शामिल देश चीन जनवादी गणराज्य है।

4. समान वस्तु

याचिकाकर्ता ने यह दावा किया है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु और संबद्ध देश से आयातित संबद्ध उत्पाद में कोई अंतर नहीं है। इन उत्पादों का आयातकों और प्रयोक्ताओं द्वारा प्रत्यक्ष रूप से आयात किया जा रहा है। उपभोक्ता घरेलू और आयातित उत्पाद को एक दूसरे की जगह पर प्रयोग कर रहे हैं। याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि ये दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं।

घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद और संबद्ध देश से आयातित उत्पाद सभी मूलभूत विशेषताओं में समान हैं और इसलिए नियमावली के अंतर्गत नियमों के अर्थ के भीतर समान वस्तुएं हैं। वर्तमान जाँच के प्रयोजनार्थ आवेदक द्वारा उत्पादित उत्पाद को उपर्युक्त नियमावली के अर्थ के भीतर संबद्ध देश से आयातित उत्पाद के समान वस्तु माना जा रहा है।

5. सामान्य मूल्य

आवेदक ने दावा किया है कि चीन जन. गण. को गैर-बाजार अर्थव्यवस्था का व्यवहार दिया जाना चाहिए और पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 के अनुसार सामान्य मूल्य का निर्धारण किया गया है। तदनुसार, चीन जन. गण. के संबंध में सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के प्रयोजनार्थ आवेदक ने जर्मनी को एक उपर्युक्त बाजार अर्थव्यवस्था वाले देश के रूप में चुना है।

किसी बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश से कीमत के एवज में आवेदक ने सामान्य मूल्य का निर्धारण नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 के अनुसार भारत में देय कीमत के रूप में किया गया है। इस सामान्य मूल्य का निर्धारण भारत में उत्पादन की लागत पर विचार करके किया गया है जिसे बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्यय और उचित लाभ को शमिल करने के लिए उचित रूप से समायोजित किया गया है।

तथापि, अलग-अलग निर्यातक इस धारणा का खण्डन कर सकते हैं और प्राधिकारी अलग-अलग निर्यातकों के बाजार अर्थव्यवस्था के दावों की संगत नियमों के अनुसार जाँच करें।

6. निर्यात कीमत

संबद्ध देश की संबद्ध वस्तुओं की निर्यात कीमत का निर्धारण डीजीसीआईएंडएस (वर्ष 2004-2005 तक की अवधि के लिए) और अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय सूचना सेवाएँ (आईबीआईएस) (अप्रैल, 2005 से दिसम्बर, 2005 तक की अवधि के लिए) से एकत्र सौदेवार आयात आंकड़ों पर विचार करके किया गया है। भारित औसत निर्यात कीमत का निर्धारण प्रत्येक संबद्ध देश के लिए आयातों की कुल मात्रा और मूल्य पर विचार करके किया गया है। कारखाना द्वारा निर्यात कीमत पर पहुँचने के लिए समायोजन समुद्री भाड़, समुद्री बीमा कमीशन, निर्यातक देश में अंतर्राष्ट्रीय परिवहन, पत्तन हैंडलिंग और पत्तन प्रभार, बैंक प्रभार, ऋण लागतें और अप्रत्यक्ष करों के आधार पर किए गए हैं।

7. पाटन मार्जिन

सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत की कारखाना द्वारा स्तर पर तुलना की गई है जिनसे संबद्ध देश के संबंध में अत्यधिक पाटन मार्जिन का पता चलता है। इस बात का पर्याप्त साक्ष है कि चीन जन. गण. में संबद्ध वस्तु का सामान्य मूल्य कारखाना द्वारा निर्यात कीमत से बहुत अधिक है जिससे प्रथम दृष्ट्या यह संकेत मिलता है कि संबद्ध वस्तुओं का संबद्ध देश के निर्यातकों द्वारा भारतीय बाजार में पाटन किया जा रहा है।

3. क्षति और कारणात्मक संबंध

आवेदक ने वास्तविक क्षति से संबंधित विभिन्न मापदण्डों के संबंध में सूचना प्रस्तुत की है। बाजार हिस्से में गिरावट, बिक्रियों में गिरावट, आयातों में समग्र रूप से और भारत में उत्पाद की मांग के संबंध में अत्यधिक वृद्धि, अत्यधिक कीमत कटौती, कम कीमत पर बिक्री जिसके कारण बाजार में कीमत में मंदी आई, लाभ निवेशों पर आय और नकदी प्रवाह में कमी जैसे मापदण्डों से सामूहिक रूप से यह संकेत मिलता है कि चीन जन. गण. से संबद्ध वस्तु के पाटन के कारण घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है। आवेदकों ने आयातों में वृद्धि की दर में बढ़ौतरी (तिमाहीवार), चीन में अत्यधिक अधिशेष अप्रयुक्त क्षमताओं, पाटित आयातों के कारण अत्यधिक कीमत कटौती जिसके फलस्वरूप आयात में और अधिक वृद्धि होने की संभावनाएँ हुई के आधार पर वास्तविक क्षति के खिलाफ़ दावा भी किया है।

4. पाटनरोधी जाँच की शुरुआत

पूर्वोक्त पैराग्राफों को ध्यान में रखते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी संबद्ध देश के मूल की अथवा यहाँ से निर्यातित संबद्ध वस्तु के कथित पाटन की विद्यमानता मात्रा और प्रभाव की जाँच करने के लिए पाटनरोधी जाँच शुरू करते हैं।

10. जाँच अवधि (पीओआई)

वर्तमान जाँच के प्रयोजनार्थ जाँच अवधि 1-12-2005 से 31-12-2005 (12 महीने) तक है। तथापि, क्षति जाँच अवधि में वर्ष 2002-2003 से 2004-2005 तक की अवधि और जाँच अवधि शामिल हैं।

11. सूचना प्रस्तुत करना

संबद्ध देश में निर्यातिकों, राजदूतावास के जरिए उनकी सरकार इस जाँच के साथ संबंधित के रूप में ज्ञात भारत में आयातकों और घरेलू उद्योग को विनिर्दिष्ट विधि और ढंग से प्रासारिक सूचना प्रस्तुत करने और अपने विचारों से निम्नलिखित पते पर निर्दिष्ट प्राधिकारी को अवगत कराने के लिए अलग से लिखा जा रहा है :—

निर्दिष्ट प्राधिकारी

पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय

नियमित एवं उद्योग मंदस्त्रय

वाणिज्य विभाग

भारत सरकार

कमरा सं. 240

उद्योग भवन, नई दिल्ली-110011

नियमावली के नियम 6(5) के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा विचाराधीन वस्तु के औद्योगिक प्रयोक्ताओं और प्रतिनिधि ग्राहक संगठन, जो पाटन, क्षति एवं आकस्मिकता के बारे में जाँच के संगत सूचना प्रस्तुत कर सकते हैं, को भी अवसर प्रदान किया गया है। कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी नीचे निर्धारित समय सीमा के भीतर जाँच के संगत सूचना प्रस्तुत कर सकता है।

12. समय सीमा

(क) सामान्य समय सीमा

वर्तमान जाँच से संबंधित कोई भी सूचना लिखित में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से चालीस दिनों के भीतर नीचे दिए गए पते पर प्राधिकारी के पास पहुँच जानी चाहिए। तथापि जिन ज्ञात निर्यातिकों एवं आयातकों को अलग से लिखा जा रहा है उनके द्वारा उन्हें अलग से लिखे गए पत्र की तारीख से चालीस दिनों भीतर सूचना प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है। यह नोट किया जाए कि निर्धारित समय सीमा के किसी विस्तार के लिए किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

(ख) बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देशों के चयन के लिए विशिष्ट समय-सीमा

जाँच के हितबद्ध पक्षकार जर्मनी, जिसे इस जाँच प्रारम्भ अधिसूचना के उपर्युक्त पैरा 5 में किए गए उल्लेख के अनुसार चीन जन. गण. के संबंध में सामान्य मूल्य के निर्धारण के प्रयोजनार्थ बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश भाना गया है कि संबंध में टिप्पणी करने की इच्छा रख सकते हैं। ये टिप्पणियाँ इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो सप्ताह के भीतर प्रस्तुत की जानी चाहिए।

13. सूचना प्रस्तुत करना

नियमावली के नियम 6(7) के अनुसार हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्राधिकारी को उपलब्ध कराई गई किसी सूचना का अगोपनीय सारांश उपलब्ध कराया जाना अपेक्षित है और यदि ऐसी सूचना उपलब्ध कराने वाले पक्षकार की राय में ऐसी सूचना का सारांश प्रस्तुत करना उचित नहीं होगा तो उसके कारण का प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है। यदि कोई हितबद्ध पक्षकार आवश्यक सूचना उपलब्ध कराने से मना करता है, अथवा किसी उचित अवधि के भीतर आवश्यक सूचना उपलब्ध नहीं करता है, अथवा जाँच में अत्यधिक बाधा डालता है तो निर्दिष्ट प्राधिकारी अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निष्कर्ष दर्ज कर सकते हैं और केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

14. सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

नियम 6(7) के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा एक सार्वजनिक फाइल रखी जाती है। हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय रूपान्तर वाली सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण किसी भी हितबद्ध पक्षकार द्वारा किया जा सकता है।

क्रिस्टी एल. फर्नांडेज, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES)

INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 1st June, 2006

Subject : Initiation of anti-dumping investigations concerning imports of Steel Wheels from China PR

F. No. 14/8/2005-DGAD.—Whereas M/s. Kalyani Lemmerz Limited, Pune and M/s. Wheels India Limited, Chennai, (hereinafter referred to as applicant) have jointly filed an application before the Designated Authority (hereinafter referred to as the Authority), in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 as amended in 1995 (hereinafter referred to as the Act) and Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 (hereinafter referred to as the Rules), alleging dumping of flat base steel wheels for commercial vehicles (hereinafter referred to as subject goods), originating in or exported from the People's Republic of China (hereinafter referred to as "subject country" or China PR) and requested for initiation of Anti Dumping investigations for levy of anti-dumping duties on the subject goods.

And, whereas, the Authority finds that sufficient *prima facie* evidence of dumping of the subject goods from the subject country, injury to the domestic industry and causal link between the dumping and injury exist, the Authority hereby initiates an investigation into the alleged dumping, and consequent injury to the domestic industry in terms of the Rules 5 of the said Rules, to determine the existence, degree and effect of any alleged dumping and to recommend the amount of anti dumping duty which, if levied, would be adequate to remove the injury to the domestic industry.

1. PRODUCT UNDER CONSIDERATION

The product under consideration in the present petition is flat base steel wheels of size 16" nominal diameter to 20" nominal diameter used in tubed tyre application in commercial vehicles, originating in or exported from China PR. Wheels are assembly of rim and disc with a demountable ring. Rims and discis are produced in separate lines and welded together to form a wheel, which is mounted on the axles of vehicles and fitted with tyres to enable vehicle movement. Commercial vehicles comprise of buses, lorries including trucks, trailers and tempos.

Wheels are defined under Chapter 87 of the Customs Tariff Act under the category Vehicles other than railway or tramway rolling stock, and parts and accessories thereof, sub-heading 870870. The Custom Classification is, however, indicative only and is in no way binding on the scope of the present investigation.

For the purpose of this investigation the product under consideration shall be described as "Wheels."

2. DOMESTIC INDUSTRY STANDING

The application has been jointly filed by M/s. Kalyani Lemmerz Limited, Pune and M/s. Wheels India Limited, Chennai, who are the sole producers of the subject product in India. The applicant has provided information relevant to the present investigations. The Authority has determined that (a) production of the applicant company constitutes a major proportion in Indian production; (b) domestic producers expressly supporting the application account for more than 50 per cent of total production of the like product produced by the domestic industry; and (c) the application has been made by or on behalf of the domestic industry.

The Authority after examining the above, determines that the applicant constitutes domestic Industry within the meaning of Rule 2 and the application satisfies the criteria of standing in terms of Rule 5 of the Rules supra.

3. COUNTRY INVOLVED

The country involved in the present investigation is the People's Republic of China.

4. LIKE ARTICLE

The applicant has claimed that there is no difference in the subject good produced by the domestic industry and the subject product imported from the subject country. The product is being directly imported by the importers and users. The Consumers are using the domestic and imported product interchangeably. Applicant has claimed that the two are technically and commercially substitutable.

The products produced by the domestic industry and imported from the subject country are identical in all essential characteristics and therefore, are like articles within the meaning of the terms under the Rules. For the purpose of the present investigation, the product produced by the applicant is being treated as like article to the product imported from the subject country within the meaning of Rules supra.

5. NORMAL VALUE

The applicant has claimed that China PR should be treated as non-market economy and has determined normal value in accordance with Para 7 of Annexure I of the Anti Dumping Rules. Accordingly, the applicant has chosen Germany as an appropriate market economy country for the purpose of establishing normal value in respect of China PR.

In an alternate to the price from a market economy third country, applicant has determined normal value as price payable in India in terms of Para 7 of Annexure I to the Rules. This normal value has been determined considering the cost of production in India, duly adjusted to include selling, general and administrative expenses and reasonable profit.

However, the individual exporters may rebut this presumption and the Authority shall examine the market economy claims of individual exporters in terms of the relevant Rules.

6. EXPORT PRICE

Export price of the subject goods from the subject country has been determined by considering transaction-wise import data collected from DGCI&S (for the period up to 2004-05) and International Business Information Services (IBIS) (for the period April, 05 to Dec., 05). Weighted average export price has been determined considering total volume and value of imports for each of the subject countries. Adjustments have been made on account of ocean freight, marine insurance, commission, inland transportation in the exporting country, port handling and port charges, bank charges, credit costs and indirect taxes to arrive at ex-factory export price.

7. DUMPING MARGIN

Normal value and export price have been compared at ex-factory level, which shows significant dumping margin in respect of the subject country. There is sufficient evidence that the normal value of the subject goods in China PR is significantly higher than the ex-factory export price indicating, *prima facie*, that the subject goods are being dumped by exporters from the subject country into the Indian market.

8. INJURY AND CASUAL LINK

The applicant has furnished information on various parameters relating to material injury. Parameters such as decline in market share, decline in sales, significant increase in imports in absolute terms as also relative to product demand in India, significant price undercutting, price under-selling leading to price depression in the market, decline in profits, return on investments and cash flow *prima facie* collectively indicate that the domestic industry has suffered material injury on account of dumping of subject goods from China PR. Applicants have also claimed threat of material injury on the grounds of increase in the rate of increase in imports, (quarter by quarter), significant surplus unutilized capacities in China, significant price under-cutting by the dumped imports thus leading to possibilities of further increased importation.

9. INITIATION OF ANTI DUMPING INVESTIGATIONS

The designated Authority, in view of the foregoing paragraphs, initiates anti-dumping investigations into the existence, degree and effect of alleged dumping of the subject goods originating in or exported from the subject country.

10. PERIOD OF INVESTIGATION (POI)

The Period of Investigation for the purpose of the present investigation is 1-1-2005 to 31-12-2005 (12 months). The injury investigation period will, however, cover the period 2002-03 to 2004-05 and the POI.

11. SUBMISSION OF INFORMATION

The exporters in the subject country, their Government through the Embassy, the importers in India known to be concerned with this investigation and the domestic industry are being addressed separately to submit relevant information in the form and manner prescribed and to make their views known to the Designated Authority at the following address :

The Designated Authority

Directorate General of Anti Dumping & Allied Duties,
Ministry of Commerce & Industry,
Department of Commerce,
Government of India,
Room No. 240,
Udyog Bhavan, New Delhi-110011

As per Rule 6(5) of Rule supra, the Designated Authority is also providing opportunity to the industrial users of the article under investigation and to representative consumer organizations who can furnish information relevant to the investigation regarding dumping, injury and causality. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation within the time limit set out below.

12. TIME LIMIT

(a) General Time Limits

Any information relating to the present investigation should be sent in writing so as to reach the Authority at the address mentioned above not later than forty days from the date of publication of this notification. The known exporters and importers, who are being addressed separately, are however required to submit the information within forty days from the date of the letter addressed to them separately. It may be noted that no request, whatsoever, shall be entertained for extension in the prescribed time limit.

(b) Specific time limit for selection of market economy third country

Interested parties to the investigation may wish to comment on the appropriateness of Germany which, as mentioned in the Para 5 above of this initiation notification is envisaged as a market economy third country for the purpose of establishing normal value in respect of the China PR. These comments must be submitted within two weeks from the date of publication of this notification.

13. SUBMISSION OF INFORMATION

In terms of Rule 6(7) of the Rules, the interested parties are required to submit non-confidential summary of any confidential information provided to the Authority and if in the opinion of the party providing such information, such information is not susceptible to summarization, a statement of reason thereof, is required to be provided. In case where an interested party refuses access to, or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Designated Authority may record findings on the basis of facts available and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

14. INSPECTION OF PUBLIC FILE

In terms of Rule 6(7), the Designated Authority maintains a public file. Any interested party may inspect the public file containing non-confidential version of the evidence submitted by interested parties.

CHRISTY L. FERNANDEZ, Designated Authority